सामाजिक गतिशीलता लोकतंत्र और आतंकवाद

डॉ. नीता वाजपेयी

संक्षेप

निर्वाचनिय बहुलतंत्र – ELECTIVE POLICHRACY

शास्त्रीय रूप में लोकतंत्र लोगों की अभिव्यक्ति को वास्तविक रुप प्रदान करता है। किंतु समसामयिक विश्व जन पुंज समाजों का विश्व है। इसमें इस शास्त्रीय उक्ति के लिये अधिक स्थान नहीं है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिये जनता द्वारा शासन है। अभिजन वादियों और नव उदार वादियों ने लोकतंत्र का अधिक व्यवहारिक रुप प्रस्तुत किया है। आज का प्रजातंत्र राजनैतिक निर्णय निर्माण शक्ति को जनता के मतों द्वारा प्रतियोगिता पूर्ण तरीके से प्राप्त करने का संस्थागत प्रयास है। वस्तुतः राजनीति सत्ता के लिये संघर्ष है और लोकतंत्र की यह विशेषता है कि वह सत्तात्मक प्रतियोगिता हेतु खुला मंच प्रदान करता है एवं निर्वाचनिय बहुलतंत्र – ELECTIVE POLICHRACY बन जाता है जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक हित संघर्ष में प्रभावशीलता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। सार्वजनिक कल्याण जैसे नारे वास्तव में मतों को आकर्षित करने के तरीके मात्र है जिनका हित संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है।

पहचान का संकट और समाज व राजनीति का अभिजनवादी रूप

इस प्रकार समसामयिक जनपुंज समाजों के लोकतंत्र में किसी अन्य तत्व की आपेक्षा प्रतियोगिता अधिक अनिवार्य तत्व है। एवं प्रतियोगी समाज में व्यक्ति का स्थान उसकी प्रतियोगिता क्षमता द्वारा निश्चित होता है। इस प्रतियोगिता में आपेक्षाकृत उपेक्षित और कम क्षमतावान लोगों के सम्मुख एक प्रकार का पहचान का संकट या प्क्म्छज्प्छळ ब्त्प्ै उत्पन्न होता है जो अनेक प्रकार की विपथगामी प्रवृत्तियों का आधार बनती है। भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र का यह विश्लेषण और भी समीचीन प्रतीत होता है। क्योंकि एक विशाल भू–भाग में निवासित विशाल जनसंख्या, जिसका लगभग एक चौथाई भाग निरक्षर है, और एक तिहाई जनसंख्या को दो वक्त भोजन भी नहीं मिलता। जहाँ राजनीतिक जागरुकता का अभाव है, जहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति अत्यंत न्यून है। ऐसे में लोकतंत्र निश्चित रूप से एक अभिजनवादी रुप ले लेता है। क्योंकि देश का शासन लगभग चालीस वर्षों तक एक प्राइवेट लि. कंपनी की तरह चलाया जाता है जिसके CEO

डॉ. नीता वाजपेयी,सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र,राज्य संपर्क अधिकारी ,राष्ट्रीय सेवा योजना छ ग शासन

गांधी नेहरु परिवार के सदस्य रहें है। करिश्माई नेतृत्व भारतीय लोकतंत्र की अपरिहार्यता बन गयी है। और इसका विस्तार दूसरे दलों तक भी हो गया है। अतः लोकतंत्र के अभिजनवादी स्वरुप के कारण राजनीतिक भर्ती की गति अत्यंत धीमी हो जाती है। फलतः बहुलवादी हित समूहों के मध्य सत्ता संघर्ष विशुद्ध अभिजनवादी स्वरूप ले लेता है जिसमें अभिजन प्रत्यावर्तन की गति भी धीमी रहती है। अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति एवं जनजाति की राजनीति इसका उदाहरण है। अभिप्राय यह है कि सत्तात्मक संघर्ष के खुले मंच के रुप में भारतीय लोकतंत्र कुछ चिरपरिचित चेहरों का अखाड़ा बन जाता है। अतः प्रतियोगिता के अवसरों की कमी असंतोषो को जन्म देती है।

यदि भारतीय लोकतंत्र के अध्ययन में व्यवस्थावादी विश्लेषण लागू करें तो स्पष्ट होता कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण अर्थात सामाजिक व्यवस्था जिसमें राजनीतिक व्यवस्था एक उपव्यवस्था के रुप में कार्य करती है, पूर्णतः परम्परागत है और धर्म जाति भाषा संप्रदाय आदि इसके मूल आधार है। जबकि राजनीतिक व्यवस्था न्याय स्वतंत्रता और समानता जैसे आधुनिक मूल्यों पर आधारित है। अतः राजनीतिक व्यवस्था और उसके पर्यावरण की अंतः क्रिया स्वस्थ रुप से नहीं चलती और अनेक प्रकार के विकारों को जन्म देती है। जैस धर्म का कारक राजनीति व्यवस्था के सामने यह संकट प्रस्तुत करता है कि कुछ संविधानेत्तर सताएँ हैं जो कानून से ऊपर है। जाति का कारक यह निश्चित करता है कि समानता केवल संविधान में है। इस अस्वस्थ अंतः क्रिया के कुछ आवश्यक परिणाम होते हैं।

1- राजनीतिक व्यवस्था को जो फिड बैंक अपने पर्यावरण से मिलता है वह पूर्णतः गैरराज. और परम्परागत होता है। फलतः राजनीतिक समाजिकरण और संस्कृतिकरण की एक दूषित प्रक्रिया जन्म लेती है जिससे राजनीति का जातिकरण माफियाकरण और हिंसात्मक आंदोलन जन्म लेते हैं। बिहार और आंध्रप्रदेश के हिंसात्मक आंदोलन को हम इस दृष्टि से देख सकते हैं।

2- राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिक्रिया भी बड़ी हद तक गैर राजनीतिक होती है। जैसे सामाजक विकास का प्रयास संवैधानिक संशोधनों द्वारा किया जाता है। समाजिक न्याय संबंधी विभिन्न प्रयास और आरक्षण आदि। संविधान निर्माताओं ने हालांकि समाजिक न्याय की जिम्मेदारी राजनीतिक व्यवस्था पर डाली थी। लेकिन साथ ही यह भी आशा जतायी थी कि कालांतर में समाजिक विकास स्वतः स्फूर्त होगा तथा राजनीतिक व्यवस्था केवल एक उत्प्रेरक का कार्य करेगी। लेकिन पांच दशकों के अनुभव से यह स्पष्ट है कि समाजिक व्यवस्था न केवल जड़ है बल्कि किसी हद तक अभी भी प्रतिक्रियावादी है। फलतः असंतोष और उसकी हिंसात्मक अभिव्यक्ति एक स्वभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है।

जहां तक भारतीय लोकतंत्र और हिंसा का संबंध है तो हिंसा की मूल उपज हमारी व्यवस्था में ही है। और इसे समसामयिक तत्वों ने ग्लोबल रुप दे दिया है। इसलिये आतंकवाद देशों की सीमाएँ लांघ चूका है। इसका अध्ययन इसी अंतर्राष्ट्रिय संदर्भ में करना उचित होगा। आतंकवाद के स्वरुप के संबंध में ALEX

SCHIMD & POLICAL TERRORISM A RESEARCH GUIDE में लिखते है कि आतंकवाद हिंसा या हिंसा की धमकी का उपयोग है तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिये संघर्ष की एक विधि है। भय दोहन जिसका लक्ष्य है। यह क्रूर है और मानवीय प्रतिमानो का पालन नहीं करता।

आतंकवाद, विद्रोह, क्रांति, गृहयुद्ध, गुरिल्लायुद्ध, अभित्रास और उग्रवाद जैसे शब्द प्रायः एक दूसरे के साथ प्रयुक्त किये जाते हैं। इन सबमें हिंसा सर्वमान्य है। म्छब्ल्ब्स्व्च्म्क्म। ळ्ैब्ब्|ऽ्ैब्म्छबै्म के अनुसार आतंकवाद एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक संगठित समूह अथवा दल अपने प्रकट उद्देश्यों को प्राप्ति मुख्य रुप से हिंसा को योजनाबद्ध उपयोग से करता है। वस्तुतः आतंकवादी कार्यवाहियों का लक्ष्य वे व्यक्ति होते हैं जो आतंकवादी समूहों के उद्देश्यामें बाधक होते हैं। यद्यपि क्रांति, विद्रोह या आतंकवाद के दीर्घकालिक उद्देश्य एक जैसे होते हैं। किन्तु इनकी तात्कालिक रणनीतियों में अंतर हो सकता है। आतंकवादी आंदोलनों की निम्नलिखित उद्देश्य प्रायः होते हैं –

1- हिंसक गतिविधियों द्वारा शासन को प्रतिक्रिया और अतिप्रतिक्रिया के लिये विवश करना जिससे जनता में शासन के प्रति घृणा और आतंकवादियों के प्रति सहनभूति प्राप्त हो।

2- जन समर्थन को संगठित करना और संभावित समर्थकों को आतंकवाद के लिये प्रोत्साहित करना।

3- अपने छिपने के लिये आधार क्षेत्रों की स्थापना करना।

हिंसा के कारण –

दार्शनिक आयाम – पुर्नजागरण काल में मेकियावली और आधुनिक युग में डार्वीन वाद ने शक्ति को जीवन का आधार माना। हीगल ओपनहीमर नित्शे सोरेल हिटलर मोसोलेनी इत्यादि ने हिंसा को राज्य का मौलिक चरित्र घोषित किया। मार्क्सवादी विचारको ने हिंसा को सामाजिक परिवर्तन का यंत्र माना। किन्तु आधुनिक आतंकवाद का मसीहा माओ–त्से–तुंग है। माओ ने गुरिल्लायुद्ध के रुप में आतंकवाद को एक सुविचारित रणनीति प्रदान की। भारत में समस्त नक्सली आंदोलनों की रणनीति माओ के इसी गुरिल्लायुद्ध और पिपुल्स वार के दर्शन पर आधारित है।

2- मनोवैज्ञानिक आयाम बीसवीं शताब्दि के अनेक लेखकों ने अत्यधिक तकनीकि प्रगति के कारण अकेले हो गये मानवीय स्वभाव को हिंसा का प्रमुख कारण माना है। अमेरिकी लेखक म्. त्ब्म्छैज्म्छ ने अपनी पुस्तक अल्केमिस्ट ऑफ रिवोलूशन में कहा है कि आतंकवादी भी हमारी तरह एक भावुक जीव होता है। किन्तु जब वह यह अनुभव करने लगता है कि उसे धोखा दिया गया है। तो उसके सामने हिंसक होने का विकल्प उपस्थित होता है। नव प्रायडवादी एरिकफ्राम ने भी अलगाव वाद को आतंकवाद का कारण माना है। राबर्ट निस्बत ने कम्यूनिटी एंड पावर में आतंकवाद का कारण साामजिक अलगाववाद को आतंकवाद का कारण माना है। इनके अनुसार मनुष्य में सुरक्षा की भावना का अभाव है और असुरक्षा की भावना उसे हिंसा के

लिये प्रेरित करती है। हरवर्ट मार्कुजे के अनुसार अलगाव का कारण है स्वतंत्रता का छिन जाना। अतः इस पराजय और कुंठा से उभरने का एक मात्र उपाय हिंसा है। इसी प्रकार का विश्लेषण सात्रे एवं एलबर्टकाम् इत्यादि ने भी प्रस्तुत किया है।

1- सीमा पर समर्थित आतंकवाद – वास्तव में शीतयुद्ध के दिनों में विदेश नीति के रुप में इसका प्रयोग महाशक्तियों ने किया। संपूर्ण हिंद चीन और अफ्रीका का गृहयुद्ध इसी का परिणाम था। वर्तमान में पाकिस्तान और चीन जैसे हमारे पड़ोसियों ने कश्मीर उत्तर पूर्व और मध्य भारत के नक्सली आतंकवादियों को सहायता प्रदान कर आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार के आतंकवाद में असंतुष्ट धार्मिक और जातिय गुटों को शत्रु देशों द्वारा सहायता और समर्थन प्रदान किया जाता है। इसमें परम्परागत युद्ध के बजाय अपेक्षतया कम खर्च वाले छद्दम युद्ध या प्राक्सीवार द्वारा शत्रु देश के क्षेत्र में एक स्थायी समस्या और अशांति उत्पन्न की जाती है।

पांच दशकों के योजनार्गत विकास में क्षेत्रीय असंतुलन स्पष्ट रुप से झलकता है। जहां पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, और तमिलनाडू का तीव्र आद्यौगिकरण हुआ है वही कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में इसका अभाव है। अतः इन राज्यों में आतंकवाद के पीछे आर्थिक असंतुलन एक बड़ा कारण है। इन राज्यों की गरीबी और बेरोजगारी ने युवकों को आतंकवाद की ओर ढकेला है।

1- बिहार और आंध्रप्रदेश के नक्सलवादी आतंकवाद के जन्म का प्रधान कारण भूमि सुधारों की ठीक से न लागू करना है। इन राज्यों में जमींदार वर्ग ने भूमि सुधार कानूनों की कमी का लाभ उठा कर सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से भूमि को अपने ही परिवारों में संरिक्षत रखा फलतः इन राज्यों में भ्ंअम ।दक भ्ंअम छवजे वाले दो वर्गों का उदय हुआ। जिसमें भूमिहिनों ने आतंकवाद का रास्ता अपनाया।

2– लाल आतंवाद

सीधे–सीधे कहा जाए तो साम्यवादी आतंकवाद या माओवादी आतंकवाद । यह तीसरी दुनिया के देशों में राज्य की विरुद्ध एक संगठित हिंसक संघर्ष खड़ा कर राज्य को परेशान करने का एक विदेशी उपकरण है । भारत में आंध्र प्रदेश से लेकर नेपाल तक का रेड कॉरिडोर का माओवादी सपना वास्तव में चीन समर्थित है , और देश के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग व सिविल सोसाइटी का एक हिस्सा उनके लिए वैचारिक आधार खड़ा करता है । वास्तव में लाल आतंक विकासशील देशों में एक गंभीर समस्या है लेकिन हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से इसमें प्रशंसनीय सफलता प्राप्त हुई है । आंध्र प्रदेश में तो यह समाप्त हो गया है छत्तीसगढ़ में भी लगभग समाप्ति की ओर है। बिहार और झारखंड में भी

लगभग समाप्त हो चुका है । किंतु लाल आतंक के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह कभी भी सर उठा सकता है।

3- जातिय (इथनिक) संघर्ष

नागा कूकि संघर्ष बोडोलैंड तथा असम का आंदोलन वस्तुतः जातिय संघर्ष का ही परिणाम है। उत्तर पूर्व भारत के छोटे–छोटे प्रजातियां समूहो को विदेशी ताकते विभिन्न स्रोतों से भड़काने और पथ भ्रष्ट करने का कार्य करती हैं जिसके पढ़े लिखे युवा उनके प्रभाव में आकर राज्य के विरूद्ध हिंसा करते हैं । इथनिक कनफ्लिक्ट का पूरे विश्व में लंबा इतिहास रहा है जो यह बताता है की जातीय संघर्षों में बाहरी शक्तियों के महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

4- राजनीतिक चेतना का विस्तार

विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक चेतना का विस्तार विपथगामी तरीके से हुआ है। जिसके कारण राजनीतिक मांगों ने उपराष्ट्रवाद का रुप ले लिया है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया मे पूर्वोत्तर राज्यों में इसीकारण समस्याएं आतीं है।

5- शासक वर्ग की संवेदन हीनता

रजनी कोठारी का यह कथन सत्य प्रतीत होता है राजसत्ता का अभिजन वर्ग ने अपहरण कर लिया है। मायरन बीनर के शब्दों में भारत में सकार दबाव गुटों के मांगों पर तब तक ध्यान नहीं देती जब तक वे अपनी शक्ति का परिचय न करा दें। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलो की सरकारों ने अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए हथियारबंदी गिरोहो से साठगांठ की, ऐसी सूचनाओं समाचार पत्रों में छपती रहीं है ।

6- चुनावी राजनीति –

चुनाव जीतने और सरकार बनाने के लालसा के आगे राष्ट्रीय हितों की बलि सामान्यता राजनेताओं द्वारा दे दी जाती है। तथा चुनावी फायदें के लिये पार्टियां आतंकवादी समूहों का समर्थन करने और लेने से नहीं हिचकती। पूर्वोत्तर की राजनीति इसका उदाहरण है।

7- शस्त्र और नार्को आतंकवाद

मादक पदार्थों कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर पर तस्करी और शस्त्र व्यापार आतंकवाद के प्रसार का एक बड़ा कारण है। मादक पदार्थों की तस्करी से ही इन्हें वह धन मिलता है जो हथियार खरीदनें के काम आता है। पूर्वोत्तर राज्यों का आतंकवाद छ।त्ब्ब ज्म्त्त्व्प्ैड का अच्छा उदाहरण है। हथियार कंपनियों और मादक पदार्थों को व्यापारियों के मध्य एक अनयोन्याश्रय संबंध स्थापित है। और इस गठजोड़ ने विश्व के सभी छोटे– बड़े आतंकवादी गुटों को परस्पर जोड़ दिया है। सर्वाधिक अफीम उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। जबकि

हेरोईन की सर्वाधिक खपत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और लैटिन अमेरिकी देशों में है। फलतः नागालैंड और मिजोरम के माध्यम से बर्मा के रास्ते से मादक पदार्थ द. पू. एशिया पहुंचाये जाते हैं, गोल्डेन ट्रायंगल कहा जाता है । नागालैंड का नागा कूकि संघर्ष वस्तुतः मादक पदार्थों के सिल्करुट पर आधिपत्य का ही संघर्ष था।

8- कानून व्यवस्था की कमी तथा नौकरशाहों की यथास्थिति वादिता ।

9- विचारधारा का संकट तथा अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना।

निष्कर्ष

1- अमेरिकी माडल की कैरेट एंड स्टिक पद्धती का पालन तथा आंतकवादियों के विरुद्ध एक सकारात्मक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

2- इसके लिये विशेष आतंकवादी निवारण दस्तों का चयन किया जाये।

3- आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिये प्रभावी उपाय किये जॉए तथा आर्थिक पैकेजों की घोषणा की बजाय विकास का ईमानदार प्रयास किया जाये।

4- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पं. बंगाल की भांति भूमि सुधारों की ईमानदारी से लागू किया जाये।

5- राजनीति के अभिजनवादी स्वरुप को कम करके राजनीतिक सहभागिता बढ़ाई जाये।

6- आवश्यक कानूनों का निर्माण कर उन्हें सही तरीके से लागू किया जाये।

8- कानून व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जाये।

9- राष्ट्रहित और दलीय हित में अंतर की सर्वाधिक आवश्यकता है अन्यथा भारत एक ैवजि ैजंजम बना रहेगा।

संदर्भ

एडेसनिक, डेविड और मैकफॉल, माइकल। "लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंकुश सहयोगियों को शामिल करना," द वाशिंगटन क्वार्टरली, खंड 29, संख्या 2 (वसंत 2006): 7-26।

एलिसन, ग्राहम टी., जूनियर, और रॉबर्ट पी. बेशेल, जूनियर। "क्या संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकता है?" राजनीति विज्ञान क्वार्टरली, खंड 107, संख्या 1 (वसंत 1992): 81-98।

बर्ड्सल, नैन्सी। "कोई नुकसान न करें: सहायता, कमजोर संस्थान और अफ्रीका में लापता मध्य," विकास नीति समीक्षा, खंड 25, संख्या 5 (सितंबर 2007): 575-598।

बिवेन्स, मैट। "ग्रेवी ट्रेन पर सवार," हार्पर (अगस्त 1997)।

बूट, मैक्स। "न तो नया और न ही नापाक: उदार साम्राज्य ने पलटवार किया," वर्तमान इतिहास, खंड 102, संख्या 667 (2003): 361-6.

ब्रॉली, मार्क आर. और बेर्ग, निकोल. "संरचनात्मक समायोजन, विकास और लोकतंत्र," अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन समीक्षा, खंड 9, संख्या 4 (2007): 601-615.
ब्रिंकले, डगलस. "लोकतांत्रिक विस्तार: क्लिंटन सिद्धांत," विदेश नीति, संख्या 106 (वसंत 1997): 111-27.
ब्राउन, स्टीफन. "विदेशी सहायता और लोकतंत्र संवर्धन: अफ्रीका से सबक," यूरोपीय जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, खंड 17, संख्या 2 (2005): 179-198.
कोएट, रोजर ए. "लोकतंत्र का प्रचार," ग्लोबल सोसाइटी, खंड 19, संख्या 4 (अक्टूबर 2005):445 - 455.
कॉक्स, माइकल, जी. जॉन इकेनबेरी और ताकाशी इनोगुची. अमेरिकी लोकतंत्र प्रचार: आवेग, रणनीति और प्रभाव. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2000.

क्रॉफोर्ड, गॉर्डन. "अफ्रीका में यूरोपीय संघ और लोकतंत्र प्रचार: घाना का मामला," यूरोपीय जर्नल ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, खंड 14, संख्या 4 (दिसंबर 2005):.571-600.

स्मिथ, टोनी. अमेरिका का मिशन: बीसवीं सदी में लोकतंत्र के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्वव्यापी संघर्ष। प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1994.

स्टेनली, डब्ल्यू.डी. "अल साल्वाडोर: लोकतंत्रीकरण से पहले और बाद में राज्य निर्माण 1980-95," थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली, 2006।
जटिल आकस्मिक संचालन के अंतर-एजेंसी प्रबंधन के लिए पुस्तिका। [वियना, वीए: थॉटलिंक, इंक.], 1998. 1 खंड (विभिन्न पृष्ठांकन)।
एचवी 551.3 एच3 1998
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद: कनाडा के लिए खतरा। [ओटावा]: कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा, [2000] 8, 8, 16 पृष्ठ।
एचवी 6431 सी3 2000
कार्टर, एश्टन बी. 2001-02. "आतंकवाद के सामने सरकार की वास्तुकला," अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, खंड 26, संख्या 2, विंटर, पृष्ठ 5-23.
कार्टर, एश्टन बी., और विलियम जे. पेरी. 1999. निवारक रक्षा: अमेरिका के लिए एक नई सुरक्षा रणनीति, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन, वाशिंगटन, डी.सी.